राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना

*शाजिया नसीब
**डॉ. कविता मित्तल

सारांश

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, में भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया है। यह पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह लेता है। इस नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान देता है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का अहम सिलसिला शुरू हो गया है। इस नीति में पठन–पाठन की पुरानी चली आ रही शिक्षक आधरित व्यवस्था की जगह विद्यार्थी–केन्द्रित नई व्यवस्था लाकर समूची प्रणाली में बदलाव लाने पर ज़ोर दिया गया है जिससे विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके और उनकी रचनात्मक क्षमता भी विकसित की जा सके। प्रस्तुत शोध पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही राजस्थान राज्य में योग्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की योजना गार्गी पुरस्कार का विश्लेषण किया गया है।

मूल शब्द – गार्गी पुरस्कार, सॉफ्रट स्किल्स, व्यावसायिक शिक्षा, परख, डिजिटल शिक्षा, विद्यार्थी–केन्द्रित ।

प्रस्तावना

भारतीय शिक्षा संरचना और प्रबंधन को नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा लंबे समय (लगभग 34 वर्ष) के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच वैश्विक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं और साथ ही शिक्षा में 'भारत–केंद्रित' नीति की आवश्यकता के बारे में देश में बहस भी हुई। वर्ष 2015 में भारत ने यूनेस्को के सतत विकास के लक्ष्य–2030 से अपनी सहमति दर्शाते हुते उसे अपनाया। इसमें परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा–4, 2030 तक, ''सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता की शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों'' को बढ़ावा देने की मांग करता है ऐसे सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए 2015 में श्री टी.एस. सुब्रमण्यनयम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। समिति ने विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार–विमर्श किया और ग्राम–पंचायत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक विस्तृत चर्चा हुई। यह नीति निर्माण का अपनी तरह का पहला प्रयोग था जिसमें नीचे से ऊपर की ओर चर्चा का दृष्टिकोण अपनाकर नीति के निर्माण से पहले विभिन्न हितधारकों के विचारों को एकत्र किया गया, उन पर व्यापक बहस की गई और एक मसौदा तैयार किया गया। जब मसौदे को चर्चा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया, तो बहुत सारे मुद्दे सामने आए। उन पर पुनर्विचार करने के लिए जून, 2017 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया गया था। कस्तूरीरंगन समिति ने समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा उठाए गए सभी सुझावों/आपत्तियों पर पुनः विचार किया और नीति का एक मसौदा तैयार किया जो 31

मई, 2018 को फिर से सार्वजनिक किया गया और आगे के सुझाव आमंत्रित किए गए। सुझावों की समीक्षा करने के बाद, समिति ने नीति को अंतिम रूप दिया और हमने जुलाई, 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के नाम से अपनी नई नीति प्राप्त की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें एक भारत–केंद्रित ज्ञान समाज विकसित करना है। एक ऐसा समाज जिसकी जड़ें अनंत भारतीय संस्कृति में हैं और दुनिया के साथ आगे बढ़ने के लिए लिए तत्पर हैं। हमारी मूल्य प्रणाली, हमारी पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, मानवता और स्थायी विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता, वैश्विक ज्ञान गुरु के रूप में हमें बढ़ावा देने और प्रतिष्ठित करने की कुंजी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ

1. उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एकाधिक प्रवेश/ निकास का प्रावधान शामिल है।
2. नई शिक्षा नीति में 10+2 के प्रारूप को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 प्रारूप में ढाला गया है। अब स्कूल के पहले पांच साल में प्री–प्राइमरी स्कूल के तीन साल और कक्षा एक और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले तीन साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा।
3. इसके बाद में तीन साल मध्य चरण (कक्षा 6 से 8) और माध्यमिक अवस्था के चार साल (कक्षा 9 से 12)। इसके अलावा स्कूलों में कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग का कोई कठोर पालन नहीं होगा, छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहें, वो ले सकते हैं।
4. उच्च शिक्षा के मद्देनज़र कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड अकैडमिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्त्तता आदि शामिल है। नई शिक्षा नीति और सुधारों के बाद 2035 तक 50 फीसद सकल नामांकन अनुपात या ग्रॉस एनरोलमेंट राशन पाने का लक्ष्य रखा गया है
5. मल्टिपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीन–चार साल बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया
6. नई शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा के लिए एक एकल नियामक (सिंगल रेग्युलेटर) का गठन किया जाएगा। कई 'निरीक्षणों' के स्थान पर अनुमोदन के लिए स्व प्रकटीकरण आधारित पारदर्शी प्रणाली के तहत काम करना शामिल है।क्षेत्रीय भाषाओं में ई–कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटफिक फोरम (NETF) शुरू किया जाएगा। देश में 45,000 कॉलेज हैं। ग्रेडेड स्वायत्तता के तहत कॉलेजों को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दी जाएगी।
7. नए सुधारों में तकनीकी और ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहां डीम्ड विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्वशाषी संस्थानों के लिए अलग–अलग नियम हैं। नई शिक्षा नीति के तहत सभी के लिए नियम समान होगा।

8. बोर्ड परीक्षाओं के महत्व के कम किया जाएगा। इसमें वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी।

9. नई शिक्षा नीति में लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि GDP का 6 फीसद शिक्षा में लगाया जाए जो अभी 4.43 फीसद है। अमेरिका की NSF (नेशनल साइंस फाउंडेशन) की तर्ज पर हम NRF (नेशनल रिसर्च फाउंडेशन) लाया जायेगा । इसमें न केवल विज्ञान बल्कि सामाजिक विज्ञानं भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। ये शिक्षा के साथ रिसर्च में हमें आगे आने में मदद करेगा।

10. सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा ली जाएगी जिसे NTA आयोजित करेगा। ये परीक्षा वैकल्पिक होगी न की ज़रूरी। इसके अलावा नै शिक्षा नीति में सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में संगीत कला और साहित्य के विषय पढ़ाये जाएंगे

11. नई शिक्षा नीति में दुनिया की नामी 100 विश्वविद्यालय एक नए कानून के तहत भारत में अपने कैंपस खोल पाएंगे। इन विश्वविद्यालयों को स्वायत्त विश्विद्यालयों की तरह ही सहूलियतें दी जाएंगी।

12. विद्यालयों में संस्कृत को भाषा के तौर पर और बढ़ावा दिया जाएगा। तीन भाषाओँ के तहत संस्कृत भाषा को भी विद्यालयों और उच्च शिक्षा में वैकल्पिक भाषा के तौर पर शामिल किया जायेगा।

13. 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदलने का महत्वकांशी लक्ष्य रखा गया है जिसमे 3000 हज़ार या इससे ज़्यादा छात्र शिक्षा पाएंगे। इस शिक्षा नीति के तहत 2030 तक हर ज़िले में कम से कम एक बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

14. इस नयी शिक्षा नीति की सबसे अहम बात ये है की इसमें रोज़गारपरक शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है। इसके तहत रोज़गारपरक शिक्षा को सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अगले दशक के दौरान धीरे धीरे लागू किया जायेगा। 2025 तक कम से कम 50 फीसदी छात्रों को इन विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में रोज़गार से सम्बंधित शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी।

इस नयी शिक्षा नीति को लाने से बेशक भारतीय शिक्षा की बदहाली में सुधार आने की उम्मीद है लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इनका कार्यान्यवयन सही तरीके से हो। भारत जैसे देश में जहां शिक्षा की बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है हर 24 छात्रों पर 1 अध्यापक मौजूद है जबकि ब्रिक्स देशों में ये आंकड़ा कहीं बेहतर है। इसके अलावा कई शिक्षा नीतियों के बावजूद हज़ारों छात्र छात्रयें शिक्षा पाने में असमर्थ हैं। इसके अलावा विद्यालयों में आ रहे सरकारी पैसे का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार भी कोई नयी बात नहीं। इस सबको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा की नयी शिक्षा नीति की घोषणा शिक्षा के सुधार की तरफ सिर्फ पहला कदम है।

गार्गी पुरस्कार

आज भी हमारे देश में कई जगहों पर लड़का–लड़की में भेदभाव किया जाता है। कहीं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण तो कही भेदभाव के कारण लड़कियों की शिक्षा में अधिक ध्यान नही दिया जाता लड़कियों की शिक्षा आठवी, दसवीं तक ही सीमित रह जाती है। जिससे बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं अपने जीवन में आगे–बढ़ने के मौको से भी वंचित रह जाती हैं। इसलिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गार्गी पुरस्कार योजना को शुरू किया गया। गार्गी पुरस्कार हर वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाले बालिका पुरस्कारों में से एक है। वृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार गार्गी वचकन नाम के महर्षि की पुत्री थी। गर्ग गोत्र में उत्पन्न होने के कारण वे गार्गी नाम से

सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। गार्गी परिश्रमी थी कठिन मेहनत कर वह विदुषी बनी शास्त्रों का अध्ययन कर दह आध्यात्मिक तत्वों की ज्ञाता बनी गार्गी ब्रहाज्ञानी होने के साथ–साथ स्वाभिमानी, निर्भय, स्वाभावकी थी इस प्रकार पुरस्कार का नाम ''गार्गी पुरस्कार'' पड़ा।

गार्गी पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राजस्थान में जितनी भी बालिकाएं रहती है और जो इस योजना के लिए पात्र है। उन सभी बालिकाओं को सरकार की तरफ से ₹3000 से ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाती है। इस योजना के तहत राजस्थान में रह रहे प्रत्येक जिले प्रत्येक ग्रामीण इलाकों शहरों आदि सभी जगह पर रहने वाली बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना का संचालन राज्य के माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है हालांकि यह योजना काफी दिनों से चलाई जा रही है लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन राजस्थान सरकार बालिकाओं के खाते में ₹3000 से लेकर ₹5000 की राशि प्रदान करती है।

राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना के लाभ

- इस योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा बालिकाओं के भविष्य को सुधारने के लिए चलाया गया ।
- राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना के तहत दसवीं कक्षा की छात्राओं को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान करी जाएगी वही 12वीं कक्षा में पढ़ रही बालिकाओं को ₹5000 की राशि प्रदान की जाएगी ।
- राजस्थान सरकार के इस प्रयास की वजह से बेटियों के भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव होगा और बेटियों को समाज में एक अच्छा दर्जा मिल पाएगा।
- इस योजना के तहत अब जो भी राशि बालिकाओं को मिलेगी वह सरकार चेक के माध्यम से प्रदान करेगी जिसे फिर आप अपने बैंक में जाकर लगाना होगा उसके बाद में आप आसानी से योजना से संबंधित जरूरी सारा रुपैया अपने बैंक खाते में ले सकोगे।

राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना के लिए जरूरी पात्रता

- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान में रहने वाली छात्राओं को ही मिलेगा यदि आप राजस्थान की मूलनिवासी नहीं हो तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है ।
- आवेदन करने वाली जो भी छात्र है उनके परिवार में किसी भी व्यक्ति के सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- जो भी छात्राएं इस योजना के तहत लाभ पाना चाहती है उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उनके पारिवारिक आय ₹100000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वार्षिक।
- ₹3000 की राशि उन बालिकाओं को प्रधानमंत्री चाहिए जो बालिकाएं दसवीं कक्षा में करीब 75 प्रतिशत अंकों से पास हुई होगी ।
- ₹5000 की राशि उन बालिकाओं को प्रदान करी जाएगी जो बालिकाएं 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंकों से ज्यादा पास हुई होगी।

- जोगी बालिका इस योजना से संबंधित लाभ पाना चाहती है उनके पास में सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा ।

गार्गी पुरस्कार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

- आवेदन करने वाली बालिका का आधार कार्ड ।
- आवेदन करने वाली बालिका का मूल निवासी प्रमाण पत्र ।
- आवेदन करने वाली बालिका का आय प्रमाण पत्र ।
- आवेदन करने वाली बालिका का 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।
- आवेदन करने वाली बालिका का बैंक खाता।
- आवेदन करने वाली बालिका का जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
- आवेदन करने वाली बालिका का मोबाइल नंबर।

राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यदि ऊपर बताई गई सभी जरूरी बातों को लेकर आप पात्र हो तो आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हो।

- इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल वेबसाइट https://rajshaladarpan.nic.in पर जाना होगा वहां पर जाकर आप इसी योजना के लिए आवेदन कर सकते हो।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको होम पेज पर गार्गी पुरस्कार के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे आपको फिर आवेदन फॉर्म दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना है यदि आप दसवीं कक्षा में हो तो आपका उसका चयन करना है और यदि आप 12वीं कक्षा में हो तो आपको उसका चयन करना है।
- इसके बाद भी यहां से छात्रा का नाम उसके माता पिता का नाम रोल नंबर मोबाइल नंबर आदि संबंधित जरूरी जानकारी मांगी जाएगी उन सभी को आपको भर देना है ।
- इसके बाद में आपको यहां पर नेक्स्ट पेज का विकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर जाना है और अगले पेज पर आ जाना है ।
- अगले पेज पर पहुंच जाने के बाद में यहां पर आपको जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- इतना कर लेने के बाद में फिर आपको सबमिट के बटन पर दबा देना है।
- इस तरीके से आप गार्गी पुरस्कार योजना कर सकते हो ।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने पर ज़ोर दिया गया। सभी के लिए समानता पर आधारित और समावेशी उत्तम शिक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था कराने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में शिक्षा तक सबकी पहुंच, सभी की भागीदारी और शिक्षण स्तर के मामले में विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को समाप्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस नीति में समानता को ही समावेशी व्यवस्था का आधार माना गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ही राजस्थान राज्य में योग्य छात्राओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की गार्गी पुरस्कार योजना स्वागत योग्य कदम है।

***शोधार्थी**
****शोध निर्देशिका**
शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई, टोक

संदर्भ ग्रंथ

1. योजना पत्रिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, फरवरी 2022, वर्ष– 66, अंक–02, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल, जे.सी., (1985). डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वाणी एजुकेशनल बुक्स, नई दिल्ली।
3. रावत पी.एल., भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगरा, यूपी, राम प्रसाद एंड संस।
4. सफाया, आर.एन., (1983). भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, दिल्ली, 9 वां संस्करण, धनपत राय एंड संस।
5. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf
6. https://www.adda247.com/upsc-exam/jaadui-pitaara-under-nep-2020-for-foundational-learning-hindi/
7. https://helpstudentpoint.com/rj/rajasthan-gargi-puraskar-yojana-2023-elegilbilty-age-detail/
8. https://rajshaladarpan.nic.in/SD3/Home/BSF/Index.aspx